भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2042

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

गोरखपुर में पीएमएवाई-यू

†2042. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के प्रत्येक वर्ष दौरान देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित और अधिवासित आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गोरखपुर में पीएमएवाई-यू के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) गोरखपुर में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत गोरखपुर में आवास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) **25.06.2015** से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए दिनांक **31.12.2025** तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए **01.09.2024** से पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि अगले पांच वर्षों में **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू **2.0** को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास

(एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.26 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। इनमें से 112.81 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरु किया जा चुका है और पिछले दस वर्षों के दौरान, 14.07.2025 तक, 93.61 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। योजना की शुरूआत से अब तक स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण किए और सौंपे गए आवासों का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2015 से गोरखपुर में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता क्रमशः 892.32 करोड़ रूपये, 852.44 करोड़ रूपये और 836.48 करोड़ रूपये है। गोरखपुर के लिए कुल 58,202 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 56,178 आवास पूरे हो चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 9,998 अनुसूचित जाति, 1,283 अनुसूचित जनजाति और 6,062 अल्पसंख्यकों के हैं। गोरखपुर में 95% प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, गोरखपुर में पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी घटक के तहत हाल ही में 5,203 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है और योजना के विभिन्न घटकों और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। मंत्रालय गोरखपुर सहित देश भर में पीएमएवाई-यू के शेष आवासों और पीएमएवाई-यू 2.0 के हाल ही में स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित और कठोर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

*****

दिनांक 31-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2042 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	सौंपे गए आवास (संख्या)**
2015-16	5,26,082	5,01,334	2,27,121
2016-17	6,35,781	3,97,309	1,28,378
2017-18	16,68,268	12,68,737	3,27,381
2018-19	22,39,333	19,86,232	17,56,393
2019-20	16,25,249	16,15,014	8,32,966
2020-21	15,61,273	18,57,383	14,47,025
2021-22	16,37,364	16,18,419	10,28,031
2022-23	9,27,084	13,16,123	15,42,379
2023-24	3,95,252	4,13,857	8,89,006
2024-25	3,52,915	2,93,042	10,34,435
2025-26	3,57,064	13,340	1,47,398
Total	1,19,25,665	1,12,80,790	93,60,513

* इसमें उस वर्ष में पूर्ण हुए आवास भी शामिल हैं जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किया गया था।

** इसमें उस वर्ष में सौंपे गए वे आवास शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पूरे हो चुके थे।